



जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

पाकिस्तान का दामन दागदार एफएटीएफ के उप-समूह ने की पड़ोसी देश को ग्रे-सूची में रखने की सिफारिश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

आतंक के लिए वित्तपोषण पर नजर रखने वाले वैश्विक निकाय वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के एक उप-समूह ने मंगलवार को सिफारिश की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट (संदिग्ध सूची) में ही रखा जाए। यह निर्णय एफएटीएफ के अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (आईसीआरजी) की बैठक में लिया गया। इस उप-समूह की मुहर लगने के बाद एफएटीएफ प्लेनरी की बैठक में इसे स्वीकृत करने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। प्लेनरी की अंतिम बैठक 21 फरवरी को होगी।

आतंक के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने में नाकाम पाया गया

तीन देशों- चीन, तुर्की और मलेशिया ने दिया पाक का साथ



विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने आइसीआरजी की बैठक में लिए गए फैसले को लेकर कहा, आतंकवाद को लेकर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 29 सूत्री काम सौंपे थे, जिनमें 11 पर काम नहीं हो पाया है। इसके अलावा बाकी कार्यों को लेकर पाकिस्तान के तर्कों से एफएटीएफ की एजेंसी संतुष्ट नहीं हो पाई है। नियमानुसार इस संस्था को पाकिस्तान को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डालने का फैसला लेना था और उसे प्लेनरी के लिए अग्रसारित करना था।

बैठक बुधवार से शुरू हो रही है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने आइसीआरजी की बैठक में लिए गए फैसले को लेकर कहा, आतंकवाद को लेकर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 29 सूत्री काम सौंपे थे, जिनमें

11 पर काम नहीं हो पाया है। इसके अलावा बाकी कार्यों को लेकर पाकिस्तान के तर्कों से एफएटीएफ की एजेंसी संतुष्ट नहीं हो पाई है। नियमानुसार इस संस्था को पाकिस्तान को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डालने का

फैसला लेना था और उसे प्लेनरी के लिए अग्रसारित करना था। लेकिन चीन, मलेशिया और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और संदिग्ध सूची के बारे में ही फैसला हो सका। एफएटीएफ ने बाकी पेज 8 पर

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा गुजरात : मिसाइल व सैटेलाइट फोन मिला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले गुजरात में पाकिस्तान से सटे इलाकों से बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल के पुर्जे और एक सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है। हांगकांग का झंडा लगा जहाज पकड़ा गया है जो मिसाइल और पुर्जे लेकर कराची जा रहा था। इन बरामदगीयों के बाद भारतीय सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों किसी बड़ी साजिश का अंदेशा कर रही हैं और जांच में जुट गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी से दो दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह करीब तीन घंटे के कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद भी जाएंगे। भारतीय कस्टम अधिकारियों ने पाकिस्तान जा रहे जहाज को कब्जे में लिया। इस पर बैलिस्टिक मिसाइल व उसके पुर्जे मिले हैं। हांगकांग के झंडे वाला यह जहाज कराची के पोर्ट कासिम जा रहा था। इस जहाज की जांच के लिए गुजरात के कांडला बंदरगाह पर रखा गया है। डीआरडीओ की टीमों ने इस जहाज की जांच शुरू कर दी है। बाकी पेज 8 पर

झुगीवासियों को जगह खाली करने का नोटिस



अमदाबाद में मंगलवार को दौरे पर ट्रंप के स्वागत के लिए लगे पोस्टरों के सामने से गुजराती महिला।

अमदाबाद, 18 फरवरी (भाषा)।

गुजरात के अमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियम के समीप झुग्गियों में रह रहे कम से कम 45 परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 24 फरवरी को निर्धारित यात्रा से पहले जगह को खाली करने का नोटिस दिया है। हालांकि अधिकारियों ने इस प्रस्तावित हाईप्रोफाइल यात्रा और नोटिस जारी किए जाने के बीच किसी तरह के संबंध से इनकार किया है लेकिन झुग्गीवासियों ने इस कदम के समय को बाकी पेज 8 पर

कोरेगांव-भीमा मामले की जांच केंद्र को नहीं सौंपेंगे : उद्धव

मुंबई, 18 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले की जांच केंद्र को नहीं सौंपेगी। वहीं ठाकरे ने यह भी साफ किया कि वह राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे। ठाकरे ने आश्वासन दिया कि वह एनपीआर के सभी कालम की जांच खुद करेंगे। पुणे के शनिवारवाड़ा में 31 दिसंबर 2017 को आयोजित एल्यार परिषद सम्मेलन में कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषण के परिणामस्वरूप हिंसा भड़की थी। महाराष्ट्र सरकार ने हाल में एल्यार परिषद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपने की मंजूरी दी थी। ठाकरे ने कहा, 'एल्यार और कोरेगांव-भीमा दो अलग विषय हैं। मेरे दलित भाइयों से जुड़ा मुद्दा कोरेगांव-भीमा का है और इसे मैं केंद्र को नहीं सौंपूंगा। मैं यह बाकी पेज 8 पर

खुलापन हिंदुओं की खासियत : भागवत

नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मंगलवार को स्तंभकारों के एक समूह के कहा कि खुलापन हिंदुओं की विशेषता है और इसे बचाए रखा जाना चाहिए। सूत्रों ने यह जानकारी दी। समझा जाता है कि भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए लेकिन किसी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। भागवत ने दिल्ली के छतरपुर इलाक में देशभर के 70 स्तंभकारों से बंद कमरे में संवाद किया और आरएसएस के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणा को लेकर चर्चा की। आरएसएस



प्रमुख के साथ बैठक में मौजूद कुछ स्तंभकारों ने इस संवाद को 'सार्थक' बताया जिसमें विविध विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। एक स्तंभकार के मुताबिक, भागवत ने कहा कि खुलापन हिंदुओं

70 स्तंभकारों से बंद कमरे में संवाद

भागवत ने दिल्ली के छतरपुर इलाक में देशभर के 70 स्तंभकारों से बंद कमरे में संवाद किया और आरएसएस के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणा को लेकर चर्चा की। स्तंभकारों ने इस संवाद को सार्थक बताया जिसमें विविध विषयों पर चर्चा हुई

की विशेषता है और इसे बचाए रखा जाना चाहिए। भागवत ने हिंदुओं को जागृत व सतर्क रहने पर जोर देते हुए कहा कि जब तक हिंदू संगठित व सतर्क बाकी पेज 8 पर

बजट में अयोध्या हवाई अड्डे के लिए पांच सौ करोड़ की राशि

जेवर हवाई अड्डे के लिए 2000 करोड़ रुपए

लखनऊ, 18 फरवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मंगलवार को चौथा बजट पेश किया। कुल 5,12,860.72 करोड़ रुपए के इस बजट में 10,967.87 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए रखे गए हैं। बजट में जेवर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा परियोजना के लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा जिसके 2023 तक चालू होने की उम्मीद है। वहीं बजट में अयोध्या हवाई अड्डे के लिए भी 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

बजट में मेट्रो नेटवर्क, हवाई अड्डों और एक्सप्रेस वे विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है इसके अलावा मार्च 2021 तक गरीबों के लिए चार लाख मकानों के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है



राज्य का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2020-21 का यह बजट राज्य विधानसभा में

कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपए, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बजट 2020-21 पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

हवाईअड्डा बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। वहीं, तुलसी स्मारक भवन के नवीकरण बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर में पंचायतों के उपचुनाव सुरक्षा कारणों से स्थगित

जम्मू, 18 फरवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) शैलेन्द्र कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य में पांच मार्च से निर्धारित पंचायत उपचुनाव को सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में 12,500 से अधिक पंचायत सीटों के लिए पांच मार्च से आठ चरणों में उपचुनाव होने वाले थे। कुमार ने कहा, 'पंचायतों के उपचुनावों को सुरक्षा कारणों से तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है।' उन्होंने कहा कि सुरक्षा मामलों को लेकर गृह विभाग से मिली जानकारी के बाद यह कदम उठाया गया। पंचायत उपचुनाव पांच से 20 मार्च के बीच आठ चरण में होने वाले थे। जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जल्ल से जल्ल उपयुक्त सभी चिंताओं को दूर करने के बाद संभवतः दो से तीन सप्ताह में चुनाव के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए जारी शेड्यूल और पहले व दूसरे चरण के चुनाव के लिए जारी की गई अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव था। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई थीं।

बिहार को पिछलग्गू नेता नहीं चाहिए : प्रशांत किशोर

पटना, 18 फरवरी (भाषा)।

बिहार में सत्ताधारी जद (एकी) से निष्कासित प्रशांत किशोर ने मंगलवार कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री यहां के दस करोड़ लोगों के नेता हैं। उनका सम्मान, शान और आन है। वे कोई मैनेजर नहीं हैं कि किसी दूसरे दल का नेता उन्हें डिप्यूट करे कि यह हमारे नेता होंगे। यह अधिकार केवल और केवल बिहार की जनता का है। प्रशांत ने कहा कि, हम लोग ऐसा नेता चाहते हैं कि जो सशक्त, समृद्ध भारत और बिहार के लिए अपनी बात कहने के वास्ते किसी का पिछलग्गू न बने। नीतीश को 'बिहार की शान' करार देते हुए उन्होंने कहा कि आज 16 सांसदों वाले दल के



बिहार के मुख्यमंत्री दस करोड़ लोगों के नेता हैं, कोई मैनेजर नहीं कि किसी दूसरे दल का नेता उन्हें डिप्यूट करे कि यह हमारे नेता होंगे

नेता को जब गुजरात के कोई नेता (अमित शाह) यह बताते हैं कि आप ही राजग के बिहार में नेता बने रहिएगा, तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती। प्रशांत ने पटना में पत्रकारों को संबोधित करते बाकी पेज 8 पर

सेना के वरिष्ठ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने कहा पीओके में लांच पैड आतंकियों से भरे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

सेना के वरिष्ठ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी 'लांच पैड' आतंकवादियों से पूरी तरह भरे हैं। संघर्षविराम उल्लंघन की आड़ में उन आतंकियों की घुसपैट कराने की पाकिस्तान की हर कोशिश का कड़ाई और दंडात्मक रूप से जवाब दिया जा रहा है। कश्मीर के श्रीनगर स्थित 15वीं कोर की रणनीतिक कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने जोर देकर कहा कि आतंकवादियों

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सभी आतंकी शिविर और लांच पैड पूरी तरह भरे हैं। ये आतंकी कैडर हमारी चौकियों पर गोलीबारी करने वाली पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैट करना चाहते हैं। -लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों



को घाटी में घुसाने और शांति में खलल डालने के प्रयासों में पाकिस्तान सफल नहीं हो पाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने कहा, 'सुरक्षाबलों ने जनमत निर्माताओं और

नागरिक संस्थाओं के परामर्शदाताओं सहित विभिन्न पक्षों के साथ समन्वय से काम कर कश्मीर घाटी में शांति को सुदृढ़ किया है।' लेफ्टिनेंट जनरल बाकी पेज 8 पर

मुंबई में 1966 के बाद फरवरी माह का सर्वाधिक तापमान दर्ज मौसम की मार पुणे और हैदराबाद में भी तापमान 30 डिग्री के पार

सर्दी ने सताया, अब गर्मी निकालेगी पसीना

नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा)।

इस साल रेकार्ड तोड़ सर्दी के बाद फरवरी में ही गर्मी ने पिछले लगभग 50 साल का रेकार्ड ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गर्मी ने उत्तर के मैदानी इलाकों में दस्तक देने से पहले तटीय क्षेत्रों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई में मंगलवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाना, इसका ताजा उदाहरण है।

विभाग के अनुसार फरवरी में 1966 के बाद मुंबई में अब तक का सर्वाधिक तापमान 17 फरवरी को 38.1 डिग्री सेल्सियस और 18 फरवरी को बढ़कर 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से सात डिग्री अधिक था।



इससे पहले मुंबई में 25 फरवरी 1966 को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। विभाग की पूर्वानुमान इकाई की प्रमुख वैज्ञानिक सती

मुंबई में 39 डिग्री पहुंचा पारा

आर्थिक राजधानी मुंबई में 17 फरवरी को 38.1 डिग्री सेल्सियस और 18 फरवरी को तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से सात डिग्री अधिक था। इससे पहले मुंबई में 25 फरवरी 1966 को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

देवी ने बताया कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में तटीय इलाकों में तापमान के स्तर में लगतार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि भारत में सामान्य तौर पर पश्चिम के तटीय

इलाकों से गर्मी की शुरुआत होती है लेकिन तापमान में इजाफे के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली हवाओं के रुख में तेजी को देखते हुए इस साल फरवरी में ही तापमान रेकार्ड स्तर पर पहुंच गया है।

मंगलवार को मुंबई का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और अहमदाबाद में 33 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पुणे और हैदराबाद में भी पारा 30 डिग्री के स्तर को पार कर गया है।

मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए विभाग ने भी ग्रीष्म लहर (हीट वेव) से बचाव के बारे में मंगलवार को परामर्श जारी कर दिया। इसके अनुसार मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस पर बाकी पेज 8 पर



मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी

दिल्ली वालों को जल्द मिलेंगी नई बसें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली की सड़कों पर बस यात्रियों के लिए बसों का संकट खत्म होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह संकट खत्म करने का आश्वासन दिया है। ज्ञात हो कि दिल्ली लम्बे समय से बसों की कमी से जूझ रही है। इस वजह से ही मार्ग पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है और यातायात जाम में भी दिल्ली वालों को फंसना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बस आ रही है और इसमें समय लगा। लेकिन आखिरकार हमने सभी बाधाएं पार कर लीं। बसें आनी शुरू हो गई हैं। वर्तमान में शहर में करीब 6000 बसें हैं। इन बसों में 3762 डीटीसी बसें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में विधानसभा

2019 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट

वाहनों में इजाफा (2016-17 व 2017-18)

टैक्सी - 0.21 फीसद (गिरावट)
दुपहिया वाहन - 7.12 फीसद
ऑटो रिक्शा - 7.28 फीसद
कार - 2.98 फीसद
अन्य यात्री वाहन - 27.56 फीसद



समय लगा, लेकिन आखिरकार सभी अटकलें दूर हो चुकी हैं। नई बसों का आना शुरू हो गया चुका है। मैं दिल्लीवालों को विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द ही बसों की दिक्कत दूर होगी।

-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

बसों को शामिल किया गया। बीते सालों में इन सभी बसों की हालत खराब हुई है और इनके ब्रेकडाउन भी बढ़े हैं।

5.81 फीसद बढ़ी है निजी वाहनों की खरीद की रफ्तार

2019 में सामने आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सरकार ने बताया कि मार्च 18 तक दिल्ली में 5.81 फीसद तक वाहनों की संख्या बढ़ी है। इस समय तक दिल्ली में 109.86 लाख वाहन थे। यह तुलनात्मक अध्ययन 2016-17 व 2017-18 के आंकड़ों के आधार पर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में दिल्ली में 1.03 करोड़ वाहन थे जो 2017-18 में बढ़कर 1.09 करोड़ हुए हैं। टैक्सी की संख्या में 0.21 की गिरावट आई है।

चुनाव में अपने घोषणापत्र 'गारंटी कार्ड' में 11000 से अधिक बसें लाने और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को 500 किलोमीटर से अधिक बढ़ाने का वादा किया था। अब तक दिल्ली सरकार केवल कलस्टर बस सेवा के तहत

बसें लेकर आ रही है। लेकिन दिल्ली में डीटीसी बसें का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान दिल्ली को सर्वाधिक नई बसें मिली थीं। डीटीसी के बढ़े में लाल-हरी



विरोध

माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से केंद्रीय बजट को जनविरोधी बताते हुए मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान माकपा नेता प्रकाश करत व भाकपा नेता डी राजा के साथ कई अन्य शामिल रहे।



प्रदूषण की समीक्षा करेगी दिल्ली सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय 20 फरवरी को समीक्षा करेंगे। इसके लिए सचिवालय में उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है। गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण में कमी लाना केजरीवाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिल्ली को हर साल भीषण प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इसका कारण दूसरे राज्यों में होने वाली आगजनी की घटनाएं और अन्य कारण भी रहते हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बैठक में सदस्यों के दौरान प्रदूषण कैसे कम किया जाए इस विषय पर पर्यावरण विभाग के उच्च अधिकारियों को अपनी योजना का खाका प्रस्तुत करने को कहा गया है। सरकार के लिए सदस्यों में प्रदूषण पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती है।

बिजली-पानी के बाद अब सड़कों की मरम्मत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली में मुफ्त बिजली-पानी की योजना के बाद सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती खस्ताहाल फ्लाइटओवरों को संभार होना। मार्गों की हालत खराब है और कई जगहों पर आधे-आधे फुट के गड्ढे हैं। इस वजह से न सिर्फ सड़कों पर जाम बढ़ता है बल्कि प्रदूषण में भी इजाफा होता है। अधिकांश मार्ग दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के तहत आते हैं। दिल्ली में 60 फुट चौड़ी सड़कें हैं, जो करीब 1260 किलोमीटर लंबी हैं।



मुख्यालय के बाहर से ही होता है आगजनी : लोक निर्माण विभाग का कार्यालय आईटीओ पर स्थित है। खस्ताहाल सड़कों की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है। आईटीओ तक पहुंचाने वाले प्रमुख फ्लाइटओवर की भी हालत भी खराब तरीके लयक नहीं।

लेकिन मार्ग जगह-जगह टूटा हुआ है। जो मार्ग पर प्रदूषण बढ़ाने और जाम लगने की वजह बन रहा है। यह हालत सिर्फ मार्ग पर ही नजर नहीं आ रही है बल्कि फ्लाइटओवर पर भी बिटुमिन टूट रहा है। जो कि वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

शास्त्री पार्क से गांधी नगर : पूर्वी दिल्ली को मध्य दिल्ली से जोड़ने के लिए इस मार्ग का प्रयोग होता है। यातायात में बदलाव होने की वजह से इस पूरे मार्ग पर अधिक यातायात है। इस मार्ग से सीधे बस अड्डा व गांधी नगर से होते हुए सीधे आईटीओ और फरीदबाद तक जाया जाता है। इसलिए इस मार्ग पर अधिक यातायात होता है। इस मार्ग पर अधिक यातायात होने की वजह मार्ग की हालत बेहद ही खस्ता है। यह खस्ताहाल मार्ग वाहन सवारों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है और जाम की बड़ी वजह भी साबित हो रहे हैं।

आप की गारंटियों पर शुरू होगी मंत्रणा, मुख्यमंत्री की बैठक आज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जनता के बीच 10 कामों का गारंटी कार्ड लेकर आई थी। यह गारंटी कार्ड दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गारंटी कार्ड को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों की बैठक लेंगे। सरकार ने गारंटी दी है कि वे निर्बाध बिजली आपूर्ति, कूड़ा रहित दिल्ली तथा अनधिकृत कॉलोनीयों के लिए मूलभूत सुविधाएं देंगे। बुधवार को होने वाली बैठक के एजेंडा में पेयजल की पाइप द्वारा आपूर्ति, सभी बच्चों के लिए शिक्षा, समाज के विभिन्न तबकों

गारंटी कार्ड में प्राथमिकता

- सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था
- सस्ती, सुलभ और बेहतर निजलाज
- 11 हजार बसें व 500 किलोमीटर मेट्रो सेवा
- वायु प्रदूषण को 3 गुना तक कम करना
- दिल्ली को कूड़े व मलबे से मुक्ति दिलाना
- महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे
- कच्ची कॉलोनीयों में बिजली,पानी, सड़क
- जहां झुग्गी-वहाँ मकान योजना लागू करना

के लिए नि:शुल्क बस सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सुरक्षा, यमुना की सफाई आदि शामिल हैं। इसमें सभी विभागों के सचिव और प्रधान सचिव शामिल होंगे।

राज्यसभा की तैयारी में प्रियंका गांधी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

लोकसभा के बीते चुनाव के बीच कांग्रेस की महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी जल्दी ही पार्टी की राज्यसभा सदस्य बनाई जा सकती हैं। प्रियंका को छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश से उच्च सदन भेजने की तैयारी है। उन्हें राज्यसभा सांसद बनाने की पुरजोर पैरवी कर रहे नेताओं की दलील है कि भाजपा से दो-दो हाथ करने के लिए सोनिया-राहुल के अलावा प्रियंका का भी संसद में होना जरूरी है। पार्टी के नेता आधिकारिक तौर पर इस मामले में कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। वहीं प्रियंका के राज्यसभा जाने की वकालत करते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने कहा कि अब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जबकि भाजपा का मुकाबला करने के लिए प्रियंका गांधी को राज्यसभा के लिए चुना जाना चाहिए। राज्यसभा सचिवालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल राज्यसभा की कुल 73 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें से चार सीटें पहले से खाली हैं जबकि 69 सीटें इस साल फरवरी से लेकर नवंबर तक खाली होंगी हैं। खाली होने वाली सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस खाते की हैं। कांग्रेस के जिन नेताओं का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है उनमें मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, कुमारी सैलजा आदि प्रमुख हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में मध्यप्रदेश-राजस्थान से तीन-तीन और छत्तीसगढ़-हरियाणा से दो-दो सीटें



मध्यप्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने कहा कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए प्रियंका को चुना जाना चाहिए।

शामिल हैं। कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार से संबंधित राज्य महाराष्ट्र से सात सीटें रिक्त हो रही हैं जबकि झारखंड से भी दो लोगों को राज्यसभा के लिए चुना जाना है। प्रियंका की दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी राज्यसभा से ही अपनी संसदीय यात्रा शुरू की थी। लिहाजा कहा जा रहा कि कांग्रेस महासचिव गांधी भी राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सूत्रों की मानें तो प्रियंका को राज्यसभा भेजे जाने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि उन्हें संसद नहीं भेजा गया तो उन्हें लोधी रोड स्थित अपना टाइप छह सरकारी बंगला खाली करना होगा। एसपीजी सुरक्षा हटा लिए जाने के बाद यह बंगला उनसे खाली कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तीनों ही नेताओं की एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी। जानकारों का कहना है कि सोनिया और राहुल का बंगला इसलिए बच गया क्योंकि वे सांसद हैं। हालांकि बताया जाता है कि प्रियंका अपने बंगले के पूरे किराए का भुगतान करती हैं।

गार्गी कॉलेज मामले में दो अन्य गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में घुसकर छात्राओं के साथ की गई छेड़छाड़ के मामले में दो अन्य लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दक्षिणी जिले की हौज खास पुलिस ने मामला प्रकाश में आने के बाद 452/354/509 और 34 आइपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले गार्गी कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कुछ बाहरी लड़के घुस आए थे जिन्होंने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ी की थी। छात्राओं ने कार्रवाई के लिए कॉलेज में प्रदर्शन भी किया था।

जामिया में हिंसा का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने विवि का दौरा किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 15 दिसंबर को हुई हिंसा का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस अपराध शाखा (एसआईटी) की एक टीम ने मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का दौरा किया। उस घटना के चार वीडियो हाल ही में सामने आए हैं, जिनमें से एक नया वीडियो सोमवार को जारी हुआ। उधर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्रों के संघ ने मंगलवार को पिछले साल 15 दिसंबर को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में घुसने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और धर्म के अपमान का

मामला दर्ज किया जाना चाहिये। दिल्ली पुलिस की विशेष जांच दल (एसआईटी) के उपायुक्त, अपराध शाखा राजेश देव के नेतृत्व में एक टीम ने पुस्तकालय का मंगलवार को दौरा किया। टीम के सदस्य छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की घटना की तहकीकात की। इस घटना में कथित पुलिस कार्रवाई के दौरान बुरी तरह से कई छात्र घायल हो गए थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक टीम के सदस्यों ने पुस्तकालय को हुए नुकसान का विश्लेषण और वीडियोग्राफी की। उन्होंने प्राकृत कार्यालय का भी दौरा किया। रविवार को सामने आए वीडियो में पुलिसकर्मियों को पुस्तकालय में छात्रों को पीटते हुए देखा जा सकता है। दो अन्य वीडियो में कुछ नकावपोश युवक पुस्तकालय में घुसते दिख रहे हैं।

क्र.सं.	बी के प्रिसिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के हिताधारकों के ध्यानार्थ	बी के प्रिसिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1.	कांफ़रेंस देनदार का नाम	22.03.2006
2.	कांफ़रेंस देनदार के निम्न की तिथि	22.03.2006
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कांफ़रेंस देनदार निर्माणाधीन / पंजीकृत है	राजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज, कानपुर (आर.जे.ओ. कानपुर)
4.	कांफ़रेंस देनदार की कांफ़रेंस पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U27104UP2006PTC031518
5.	कांफ़रेंस देनदार के पंजीकृत कार्यालय (शिफ्ट कोड हो तो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : बी-80, उद्योग कुंज, साइट-V, पनको, कानपुर-208022, यूपी
6.	कांफ़रेंस देनदार के संबंध में न्याय शोध अधिनियम अधिनियम तिथि	18.05.2019 (CIRP) हुकू होने की तारीख से 180वा दिन + CIRP में 90 दिन का विस्तार
7.	कांफ़रेंस देनदार के संबंध में न्याय शोध अधिनियम अधिनियम तिथि	10.02.2020 (आदेश की प्रती को आरपी/परिणामक को 18.02.2020 स्थिति किया गया)
8.	परिणामक के रूप में कार्यरत न्याय शोध अधिनियम अधिनियम का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	नाम : पवन के गोयल पंजीकरण संख्या : IBB/PA-001/IP-00203/2017-2018/10392
9.	परिणामक का पता और ई-मेल, जैसा कि बॉर्ड में पंजीकृत है	पता : 204बी और 207, उपनगर टॉवर कॉम्प्लेक्स, 13, और विहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली - 110092 ईमेल : pawankgoyal@gmail.com
10.	परिणामक के लिए पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पते और ईमेल, यदि क्रमांक 9 में दिए गए पते से अलग है	पता : सी-11, दूसरी मंजिल, राज नगर आर.डी.सी. गांधीबाबाद, यूपी - 201 002 ईमेल : liquidation.beekay@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अनंतिम तिथि	20.03.2020 (अंतिम इस सार्वजनिक घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन)

एन.दादा संस्था की जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिनियम, इलाहाबाद पीठ ने 10 फरवरी, 2020 को बी के प्रिसिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के परिणामक का शुरू करने का आदेश दिया है। परिणामक के आदेश की प्रती, परिणामक को 18.02.2020 को स्थिति की गई थी।

बी के प्रिसिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के हिताधारकों को इनके द्वारा 20 मार्च 2020 को या उससे पहले समूह के साथ अपने दावे परिणामक के पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसे की मद संख्या 10 के समूह उल्लेख किया गया है।

विधायक लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी हिताधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा जमा कर सकते हैं।

क्यास या धारा 3 प्रमाण प्रस्तुत करने पर चुनौती किया जा सकता है।

हस्ता/-
पवन के गोयल
परिणामक

दिनांक : 18.02.2020
स्थान : कानपुर

बी के प्रिसिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : IBB/PA-001/IP-00203/2017-2018/10392



ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ करें अपनी शिकायत दर्ज

कॉल करें
24x7 हेल्पलाइन
नंबर पर
155271



कॉल करें अथवा अपनी शिकायत
<https://ngms.delhi.gov.in/> पर दर्ज करें

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें: cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in | लिखें: पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

तुरंत पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर पर कॉल करें

पुलिस को सूचना देने के लिए 1090 पर कॉल करें



हरिद्वार कुंभ मेले में होंगे 10 स्नान पर्व

हरिद्वार में लगने वाला 2021 का कुंभ मेला 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और 30 अप्रैल 2021 तक 4 महीने तक चलेगा। इसमें 4 शाही स्नान पर्व और शेष 6 स्नान पर्वों सहित कुल 10 स्नान पर्व होंगे। कुंभ मेले का मुख्य स्नान पर्व 14 अप्रैल को शेष सकांतिक दिन होगा। इस स्नान पर्व को अमृत गंगा स्नान पर्व भी कहा जाता है। इसका पौराणिक महत्व है। इस दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। हर की पैड़ी हरिद्वार की प्रबंध कारिणी संस्था श्री गंगा सभा के अध्यक्ष पंडित प्रदीप झा और महामंत्री पंडित तन्मय वशिष्ठ द्वारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पदाधिकारियों तथा कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर स्नान पर्वों की सूची तैयार की गई।

उत्तराखंड

कुंभ मेले क्षेत्र का दायरा फैलेगा, बढ़ेंगे तीर्थयात्री

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

हरिद्वार में 2021 में लगने वाले कुंभ मेले में इस बार 15 करोड़ तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है जबकि 2010 के कुंभ में 9 करोड़ तीर्थयात्री 4 महीने की अवधि तक चले मेले में आए थे। वहीं, इस बार पिछले कुंभ मेले की तुलना में मेला क्षेत्र का अधिक विस्तार किया जा रहा है।

इस बार कुंभ मेले में और अधिक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पिछले कुंभ मेले के मेला क्षेत्र 630 हेक्टेयर की तुलना में 2021 में 1454 हेक्टेयर का प्रयोग किया जाएगा। पिछले कुंभ में 210 हेक्टेयर की तुलना में कुंभ 2021 में लगभग 550 हेक्टेयर में 150 से 200 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे।

सभी सैन्यासियों की सुविधाओं के लिए गौरी शंकर क्षेत्र स्थान घाट का निर्माण किया जा रहा है। इस बार कुंभ मेले के मेला क्षेत्र 1454 हेक्टेयर में मेला होगा। इसमें 583 हेक्टेयर में पार्किंग, 874 हेक्टेयर में एरिया कैम्पिंग के लिए योजना बनेगी। पिछले कुंभ की तुलना में 9 सेक्टर अधिक बनाए जाएंगे।

कुंभ मेला क्षेत्र को 41 सेक्टरों में बांटा जाएगा। इस बार जो नए सेक्टर बनाए गए हैं, उनमें शिवालिक नगर, जगजीतपुर, गौरीशंकर द्वितीय, कांगड़ी पार्क, श्यामपुर, ऋषिकेश, तपोवन में पार्किंग सेक्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा देवपुरा पहातमाल, सप्तसरोवर को कैम्पिंग के लिए चुना गया।

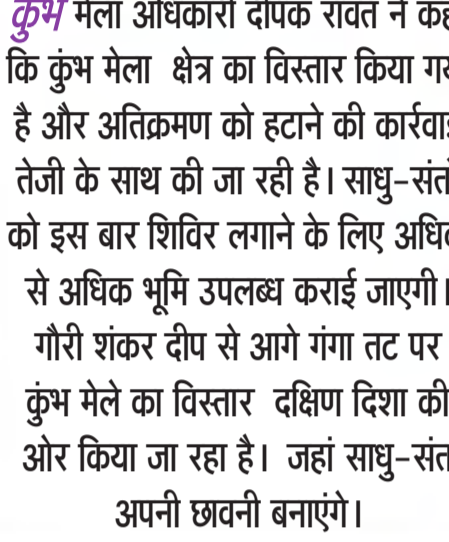
कुंभ मेले में दिव्यांगों के लिये इको फ्रेंडली लो फ्लोर बस और दिव्यांग घाट बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए पिंक सेवा ई-रिक्शा, ऑटो चलेंगे। इसको स्वयं महिलाएं संचालित करेंगी।

इस बार राज्य सरकार कुंभ मेले को लेकर अधिक गंभीर दिखाई दे रही है। कुंभ मेला अधिकारी और कुंभ मेला महा निरीक्षक की नियुक्ति पिछले अन्य कुंभ के मुकाबले काफी पहले कर दी गई। मुख्यमंत्री स्तर पर अब तक छह बैठकें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ हो चुकी है।

मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, कुंभ मेला अधिकारी तथा मेला पुलिस महानिरीक्षक के स्तर पर भी 12 बैठकें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरि और अन्य साधुओं के साथ खुद एक बार कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरि का कहना है कि वे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कराए जा रहे कुंभ



मुख्यमंत्री त्रिवेद सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेला कार्यों में किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी। इस साल 30 नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों को निश्चित ही पूरा करा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले का मैक्रो और माइक्रो लेवल पर प्लान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए।



कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया है और अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही तेजी के साथ की जा रही है। साधु-संतों को इस बार शिविर लगाने के लिए अधिक से अधिक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौरी शंकर दीप से आगे गंगा तट पर कुंभ मेले का विस्तार दक्षिण दिशा की ओर किया जा रहा है। जहां साधु-संत अपनी छावनी बनाएंगे।



कुंभ मेला पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने कहा कि ट्रैफिक को निर्बाध रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक मेला योजना के तहत हर 10-15 किलोमीटर पर जेसीबी इत्यादि वाहन का सेटअप रखा जाएगा। गंगा घाटों पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिये सेफ्टी ऑडिट कराई जाएगी। ऋषिकेश, मोतीचूर, बैरागी कैम्प, धीरवाली, दश द्वीप, ऋषिकुल में अस्थायी बस अड्डे बनाने का प्रस्ताव रखा गया। पिछले कुंभ में 210 हेक्टेयर की तुलना में कुंभ 2021 में लगभग 550 हेक्टेयर में 150 से 200 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे।

सभी सैन्यासियों की सुविधाओं के लिए गौरी शंकर क्षेत्र स्थान घाट का निर्माण किया जा रहा है। इस बार कुंभ मेले के मेला क्षेत्र 1454 हेक्टेयर में मेला होगा। इसमें 583 हेक्टेयर में पार्किंग, 874 हेक्टेयर में एरिया कैम्पिंग के लिए योजना बनेगी। पिछले कुंभ की तुलना में 9 सेक्टर अधिक बनाए जाएंगे।

कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट हैं और इस बार राज्य सरकार ने समय रहते अन्य कुंभ मेलों के मुकाबले कुंभ मेले से जुड़े अधिकारियों नियुक्ति समय पर कर ली। इससे कुंभ कार्यों में गति आई है।

हरिद्वार कुंभ एक वर्ष पहले लगेगा
ज्योतिष गणना के हिसाब से इस बार हरिद्वार कुंभ मेला 12 वर्ष की बजाय एक वर्ष पूर्व यानी 11 वर्ष में होगा। ज्योतिष विद् डॉक्टर पंडित प्रतीक मिश्र पुरी का कहना है कि ज्योतिष गणना के हिसाब से गुरु बृहस्पति ग्रह को एक राशि को पार करने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है। बारहवें वर्ष में गुरु बृहस्पति ग्रह पुनः उस राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में वे 12 वर्ष में आए थे। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब तीर्थ नगरी

हरिद्वार में कुंभ भरता है। ज्योतिष शास्त्र के सूक्ष्म गणित के अनुसार गुरु बृहस्पति ग्रह को 12 ग्रहों की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 11 माह 27 दिन का समय लगता है। इसके अनुसार 58 दिन का अंतर पड़ जाता है। सातवें कुंभ के अंतराल में आठवां कुंभ एक वर्ष पहले पड़ता है। इस तरह हरिद्वार में 2021 के कुंभ से पहले 1938 में एक साल पहले यानी 11वें वर्ष में कुंभ पड़ा था। ज्योतिष शास्त्र में की गई गणना के अनुसार पिछले एक हजार साल में केवल हरिद्वार में ही कुल 85 कुंभ पड़े हैं। एक हजार वर्ष में हरिद्वार में पड़ने वाले 85 कुंभ में से अब तक 10 कुंभ 11 साल में पड़े हैं और 2021 में हरिद्वार में 11 वर्ष में पड़ने वाला कुंभ मेला 11वां है।

मछली उत्पादन बढ़ाने को खास एंबुलेंस का सहारा

शंकर जालान
कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में मुख्य भोजन मछली-भात (चावल) है। धान के उत्पादन में बंगाल की स्थिति अन्य राज्यों से कहीं बेहतर है। अब मछली उत्पादन में भी राज्य सरकार पहले पायदान पर जाने के लिए कोशिश कर रही है। राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सूबे की सरकार एक अनोखी पहल करेगी है, जिसके तहत मछलियों के लिए एक खास तरह की एंबुलेंस चलाई जाएगी। इस एंबुलेंस में चिकित्सकों की देखरेख में मछलियों का समुचित इलाज किया जा सकेगा। फिलहाल प्रयोग के तौर पर दक्षिण चौबीस परगना जिले से सुंदरवन में एक ऐसी एंबुलेंस चलाई जा रही है, जिसमें मछलियों के इलाज की पूरी व्यवस्था है।



एंबुलेंस



एंबुलेंस में चिकित्सा सुविधा

इसके अलावा एंबुलेंस के अंदर की मछलियों की सामान्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं अत्याधिक अस्वस्थ मछली को जीवित अवस्था में प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था इस खास एंबुलेंस में है।

एंबुलेंस की खासियत का जिक्र करते हुए घोष ने कहा कि इसके अंदर पानी की जांच के लिए अलग-अलग कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया भी मौजूद है। आने वाले दिनों में इस तरह की एंबुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिश एंबुलेंस सुंदरवन के मछुआरों के लिए वरदान तो साबित होगी ही साथ ही मछली उत्पादन का ग्राफ भी बढ़ेगा।

वहीं, सुनियम रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक उदय कुमार लाहिड़ी ने बताया कि उन्होंने इस तरह की एंबुलेंस पहली बार देखी है जो काफी अलग है और इससे मछुआरों को काफी फायदा होगा। खास तरह की यह एंबुलेंस मछलियों के इलाज में निःसंदेह कारगर साबित होगी।

कैंसर पीड़ित बच्चों को मिले पढ़ाई-जीविका का सहारा

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली।

बच्चों में होने वाले कैंसर का अब पूरी तरह से इलाज संभव है। बशर्तें इसका समय पर इलाज शुरू हो और नियमित रूप से मरीज डाक्टरों के संपर्क में रहे। इसमें इलाज के खर्च के अलावा मरीज के परिवारों की अस्पताल तक पहुंच व आवाजाही में होने वाले खर्चें सहित बच्चे के पोषण व हाईजिन पर होने वाला भारी भरकम खर्च है आज बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही नियमित निगरानी व कैंसर के बचे मरीजों के आगे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी नीतिगत फैसले की दरकार है। एम्स के बाल रोग विभाग की ओर से सरकार से यह पैरवी करने की तैयारी भी है कि इन बच्चों को पढ़ाई व जीविका में विकलांग बच्चों की तरह वरीयता देने का प्रावधान किया जाए।

एम्स के बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ एके देववारी ने बताया कि कैंसर के कुल मरीजों में से पांच फीसद मरीज बच्चे होते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों में होने वाले कैंसर में से 50 फीसद कैंसर अस्थिमज्जा से जुड़ा यानी खून या लिम्फोड में होने वाला कैंसर होता है। वहीं 50 फीसद कैंसर ट्यूमर के रूप में होता है। उन्होंने बताया कि जहां बड़ों में होने वाले कैंसर में बचाव के उपाय करने से कमी लाई जा सकती है वहीं बच्चों के कैंसर को

होने से रोकना अभी तक नामुमकिन है। बच्चे के विकास के साथ ही इसके लक्षण उभरने लगते हैं। उन्होंने बताया कि आज 30 साल पहले तक खून में होने वाले कैंसर से बच्चे की मौत निश्चित थी, वही आज 30 फीसद बच्चे पूरी तरह से बचाए जा सकते हैं। 10 साल में यह और बेहतर नतीजे देगा।

डॉ देववारी ने कहा कि बच्चों में होने वाले कैंसर के सफल इलाज जहां सुकून देता है वहीं इलाज के साइड इफेक्ट के तौर पर पैरिन्याज की खराबी से मधुमेह या हार्मोन संबंधी गड़बड़ी, बच्चों के जननार्गों के विकास पर असर या स्टेराइड का बच्चों की हड्डियों के विकास पर असर आने का खतरा रहता है। इसके अलावा एन्थ्रासाइकलिन नामक दवाओं से हृदय संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। रेडियोथेरेपी का भी गुदुं सहित तमाम अंगों पर असर बना रह सकता है। डॉ देववारी ने कहा कि आयुष्मान भारत व राष्ट्रीय आरोग्य निधि से इलाज के लिए तो मदद मिल भी जाती है लेकिन बाकी खर्च परिवारों को उठाने पड़ते हैं जो काफी महंगा पड़ता है। वे विभाग की ओर से सरकार के पास प्रस्ताव भेजने वाले हैं कि ऐसे बच्चों के इलाज के दौरान मुफ्त रहने, पोषण, बड़े होने पर पढ़ाई

व नौकरी में दिव्यांगों की तरह वरीयता देने का नीतिगत प्रावधान करें ताकि बीमारी से बचे बच्चे जीविका के संघर्ष में हार न जाएं। बाल कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ रचना सेठ ने कहा कि इन मरीजों में होने वाले कैंसर का पहले 30 फीसद मामलों में पूरी तरह इलाज हो पाता था। लेकिन अब इसकी सफलता दर में इजाफा हुआ है। नई तकनीक व इलाज में और बेहतर आने के बाद उम्मीद है कि हम ऐसे 60 फीसद मरीजों को बचा सकेंगे।

बाल कैंसर रोग दिवस के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में कैंसर का सफल इलाज करा चुके बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इन बच्चों में शामिल रितु (10) ने बताया कि उनका एक तरह के लिम्फोमा का 2017 में इलाज पूरा हुआ। अब वह पूरी तरह ठीक है लेकिन इलाज के कारण अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई है। कैंसर से जीत चुकी चारु (12) ने बताया कि वह पुलिस सेवा में जाना चाहती है। जबकि कैंसर को मात दे चुकी अंजलि शिक्षक बनने का सपना पाते हैं। वहीं 12 साल के अमन सफल इलाज के बाद समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाए हैं।

केन किड्स की सुमन आनंद ने बताया कि नियमित तौर पर बड़े शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचने व रहने पर भारी भरकम खर्च आता है। इलाज पर आने वाला खर्च तो सरकार की ओर से मिल जाता है लेकिन रहने के खानपान का आने जाने का कोई इंतजाम नहीं होने से मरीज बीच में निगरानी छोड़ देते हैं।



देश

शिक्षकों के एक लाख पद खाली

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान के शिक्षा महकमे में शिक्षकों के पद खाली रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और स्कूली शिक्षा की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं पर अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों का निर्धारित कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है।

शिक्षा विभाग में शिक्षकों के एक लाख पद खाली हैं। सरकार ने शिक्षकों की जो भर्ती निकाली है उनमें सिर्फ 34 हजार अध्यापकों की भर्तियां होंगी। इसके कारण अगले शिक्षा सत्र में फिर से स्कूलों में अध्यापकों का टोटा रहेगा।

राज्य के शिक्षा विभाग में तीन साल से लगातार भर्तियां निकाल कर शिक्षक और कमचारियों के पद भरे जा रहे हैं। इसके बावजूद हर वर्ष शिक्षकों की कमी का सामना सरकारी स्कूलों को करना पड़ रहा है।

शिक्षकों की कई भर्तियां तो कानूनी दावपेंच में फंसी हुई हैं। इस वर्ष सरकार ने 34 हजार पदों पर अध्यापकों की भर्ती की घोषणा कर दी है। इनमें से तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के 31 हजार और स्कूली व्याख्याताओं के तीन हजार पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा विभाग में खाली पदों के मुकाबले भर्ती के पद बेहद कम हैं। इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होगा। उनकी पढ़ाई फिर अगले वर्ष पूरी नहीं हो पाएगी और हर स्कूल में शिक्षकों की कमी रहेगी।

मौजूदा समय में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में 5 लाख 10 हजार 285 पद हैं। इनमें से 4 लाख 14 हजार 177 पद ही भरे हुए हैं। इसके हिसाब से 96 हजार 108 पद रिक्त चल



वर्ष 2016 में तृतीय श्रेणी के 15 हजार शिक्षकों की तो वर्ष 2018 में 54 हजार पदों पर भर्ती की गई थी। इसी तरह से वर्ष 2015 में 13 हजार 98 व्याख्याताओं के पदों पर भर्ती की गई थी। वर्ष 2018 में पांच हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी जो अभी चल रही है।

रहे हैं। इन खाली पदों में से 68 हजार 370 माध्यमिक शिक्षा और 27 हजार 738 पद प्रारंभिक शिक्षा में रिक्त हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश में हर वर्ष नये विद्यालय खोलने के साथ ही मिडिल और सेकेंडरी स्तर के स्कूल लगातार

क्रमोन्नत होते हैं। इसके कारण भी शिक्षकों के पदों पर हमेशा कमी बनी रहती है। प्रदेश में तीन वर्षों में शिक्षकों की भर्तियां निरंतर की जा रही हैं।

वर्ष 2016 में तृतीय श्रेणी के 15 हजार शिक्षकों की तो वर्ष 2018 में 54 हजार पदों पर भर्ती की गई थी। इसी तरह से वर्ष 2015 में 13 हजार 98 व्याख्याताओं के पदों पर भर्ती की गई थी। वर्ष 2018 में पांच हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी जो अभी चल रही है।

वर्ष 2016 में तृतीय श्रेणी के 15 हजार शिक्षकों की तो वर्ष 2018 में 54 हजार पदों पर भर्ती की गई थी। इसी तरह से वर्ष 2015 में 13 हजार 98 व्याख्याताओं के पदों पर भर्ती की गई थी। वर्ष 2018 में पांच हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी जो अभी चल रही है।

दूसरी तरफ शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार बेरोजगार शिक्षकों को रोजगार देने के प्रति गंभीर है। इसलिए तृतीय श्रेणी के 31 हजार और व्याख्याताओं के तीन हजार पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी गई है। सरकार पिछली भर्तियों में आई परेशानियों को दूर करने में लगी हुई है। इसके साथ ही रीट का आयोजन 2 अगस्त को होगा। इसके पैटर्न को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके बाद शिक्षकों की कमी को काफी हद तक दूर कर लिया जाएगा।

